Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:12(4), December, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के परिप्रेक्ष्य में स्वदेशी वस्तुओं की संभावनाएं, चुनौतियां एवं जनमानस के रुख का अध्ययन (मध्यप्रदेश के संदर्भ में)

डॉ.मौसमी राय

[1]सहायक प्राध्यापक,

गवर्नमेंट एम.एल.बी. गर्ल्स पी.जी. ऑटोनॉमस पी.जी. कॉलेज भोपाल,

सारांश :-

दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की टैक्स व्यवस्था इन दिनों बड़े बदलाव की ओर आगे बढ़ रही है। एक ओर जहां सरकार ने जीएसटी के स्लैब में बदलाव करके भारतीय बाजार को गति देने की पहल प्रारंभ की है, वहीं अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ ने एक नई बहस छेड़ दी है। अब केंद्र सरकार द्वारा स्वदेशी वस्तुओं की संभावनाओं को तलाशने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनमानस अमेरिकी टैरिफ, जीएसटी स्लैब में बदलाव और स्वदेशी वस्तुओं के बारे में क्या रुख अपनाता है? इस शोध अध्ययन में विश्लेषण करने की कोशिश की गई है। इस शोध अध्ययन के उद्देश्य में भारत पर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ, जीएसटी स्लैब में बदलाव, टैक्स राहत, स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल से अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव और जनता के मन में स्वदेशी अभियान के प्रति समझ को शामिल किया गया है। इस अध्ययन में मध्यप्रदेश में निर्यात वृद्धि की ऐतिहासिक बढ़त और टैरिफ के प्रभाव का अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन की मैथोडोलॉजी में उद्देश्यपरक सैंपलिंग को शामिल किया गया है। प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए प्रश्नावली को आधार बनाया है, जिसके लिए गूगल फॉर्म को विभिन्न नागरिकों से भरवाया गया है। युवाओं, शिक्षाविदों आदि से पर्सनल चर्चा की गई है। जबकि द्वितीयक तथ्यों के लिए विभिन्न शोध जर्नल, इंटरनेट रिपोर्ट, समाचार रिपोर्ट, शोध ग्रंथों का अध्ययन किया गया है। शोध के परिणामों में बताया गया है कि फिलहाल अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से बाजार में बहुत कम, लेकिन प्रभाव जरूर दिख सकते हैं। लेकिन सरकार द्वारा जीएसटी के स्लैब में बदलाव से बाजार को गति मिलने की संभावना है। स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण और बाजार में उसकी तीव्र, आसान पहुंच से अमेरिकी टैरिफ के बदलाव को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। स्वदेशी अभियान का भारतीय जनमानस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता दिख रहा है।

मुख्य शब्द :- टैरिफ, स्वदेशी, संभावनाएं, चुनौतियां, जनमानस

प्रस्तावना :-

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दुनिया भर के देशों से अमेरिका पहुंचने वाले सामानों पर टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका का तर्क है कि इससे वहां विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और नौकरियां पैदा होंगी, लेकिन आर्थिक जानकारों, आलोचकों ने दावा किया है कि ऊंची कीमतें और वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचने की आशंका है। दरअसल, टैरिफ आयातित वस्तुओं पर लगाए जाने वाला एक प्रकार का कर हैं। यह टैक्स आमतौर पर किसी वस्तु के मूल्य का 1% होता है। 10 डॉलर के उत्पाद पर 10% टैरिफ का मतलब होगा कि उस पर 1 डॉलर का कर लगेगा - जिससे कुल लागत 11 डॉलर हो जाएगी। यह

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:12(4), December, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

कर विदेशी उत्पाद लाने वाली कम्पनियों द्वारा सरकार को दिया जाता है। अगस्त में, एक अमेरिकी अपील अदालत ने फैसला सुनाया कि ट्रम्प द्वारा घोषित अधिकांश टैरिफ अवैध थे। व्यापार वार्ता में देरी के बाद, अमेरिका ने अगस्त में दर्जनों देशों के लिए नई टैरिफ दरें लागू की गईं। इनमें भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ - जिसमें रूस के साथ व्यापार पर 25% जुर्माना भी शामिल है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न देशों पर थोपे गए टैरिफ के बाद अमेरिकी सरकार का टैरिफ राजस्व तेज़ी से बढ़ा है। आधिकारिक अमेरिकी आँकड़े बताते हैं कि जून 2025 में यह 28 अरब डॉलर हो जाएगा, जो 2024 के मासिक राजस्व का तीन गुना है। भारत में अमेरिकी टैरिफ का कितना असर होगा? इस सवाल का जवाब आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, कुछ रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि भारत-अमेरिका की बीच व्यापार को लेकर डील अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आसियान शिखर सम्मेलन से पहले समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ में उल्लेखनीय कमी करते हुए टैरिफ 50% से घटकर 15-16% कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत रूस से अधिक तेल आयात कर रहा है, इसलिए टैरिफ बढ़ा रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बयान में कहा था कि भारत अमेरिका से लगातार कच्चे तेल की खरीद को बढ़ा रहा है। साथ ही, बताया कि हम रूस के सबसे बड़े क्रूड ऑयल खरीदार नहीं हैं। जयशंकर ने कहा कि भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार नहीं है, बल्कि वह चीन है। उन्होंने कहा था कि हम रूसी एलएनजी के सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं, बल्कि वह यूरोपियन यूनियन है। हम वह देश नहीं हैं, जिसका 2022 के बाद रूस के साथ व्यापार में सबसे बड़ा उछाल आया। मुझे लगता है कि ऐसे कुछ देश दक्षिण में हैं। अमेरिका भले कुछ भी करे, लेकिन इस बीच भारत का पड़ोसी देश चीन बड़ा बाजार बनकर उभरा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच भारत ने चीन को 8.41 अरब डॉलर के सामान निर्यात किए हैं, जो पिछले साल की समान अवधि में 6.90 अरब डॉलर थे। यह लगभग 22% की बड़ी उछाल है। अगस्त में अमेरिका द्वारा बढ़े टैरिफ के बाद सितंबर 2025 में चीन को निर्यात में 34% की जबरदस्त छलांग लगाई है, जो 1.09 अरब डॉलर से बढ़कर 1.47 अरब डॉलर तक पहुंच गई। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में भारत का चीन को निर्यात करीब 22% बढ़ा है।इस बीच कई पहल सरकार द्वारा प्रारंभ की गई हैं। भारत सरकार अर्थव्यवस्था की निर्यात पर निर्भरता कम करने के लिए 'स्वदेशी' मंत्र पर जोर दे रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीयों से "स्थानीय के लिए मुखर" होने का आह्वान कर रहे हैं।

उद्देश्य :-

1. अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का भारत की अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन करना?
2. जीएसटी स्लैब में बदलाव से भारतीय बाजार की गतिशीलता और टैरिफ के प्रभाव का अध्ययन करना?
3. मध्यप्रदेश के निर्यात में वृद्धि की रिपोर्ट का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना?
4. स्वदेशी वस्तुओं की संभावनाओं और उसकी चुनौतियों के बारे में जनविचार का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना?

शोध प्रविधि :-

प्रस्तुत शोध अध्ययन "अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के परिप्रेक्ष्य में स्वदेशी वस्तुओं की संभावनाएं, चुनौतियां एवं जनमानस के रुख का अध्ययन (मध्यप्रदेश के संदर्भ में)'' को पूर्ण करने के लिए उद्देश्यपरक (नमूना चयन) सेंपलिंग का चयन किया है। प्राथमिक तथ्यों के एकत्रितकरण के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है, उनमें प्रश्नावली भी एक

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:12(4), December, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

है। वर्तमान में इंटरनेट और टेक्नोलाजी ने प्रश्नावली को और भी आसान बना दिया है। मेरे द्वारा गूगल फार्म से बनाई गई प्रश्नावली को चयनित उत्तरदाताओं को ई-मेल और वाट्सएप के माध्यम से भेजा गया। इनमें से शिक्षक, वाणिज्य विषयों के जानकार, आम नागरिक, मीडिया प्रतिनिधि, कॉलेज विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी और जागरूक नागरिकों से प्रश्न पूछे गए। प्रश्नावली में कुछ 15 प्रश्न पूछे गए। 60 उत्तरदाताओं से प्रश्नावली का जवाब लिया गया। गुणात्मक प्रविधि से प्राप्त उत्तरों को मात्रात्मक स्वरूप प्रदान कर निम्नलिखित आधारों पर उनकी विवेचना की गई। इसके अलावा इस शोध कार्य को पूर्ण करने के लिए द्वितीयक तथ्यों के संकलन के लिए विश्वविद्यालयों के पुस्कालयों में आने वाले प्रकाशन, शोध जर्नल, पुस्तकें, सरकारी रिपोर्ट, टीवी मीडिया रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। समय-समय पर विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट, डीडी न्यूज सहित अन्य समाचार चैनलों में आने वाली खबरें, चर्चाएं, पीआईबी की रिपोर्ट आदि का अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया। इसके पश्चात प्राथमिक एवं द्वितिय तथ्यों का विश्लेषण करके परिणाम निकालकर निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

विश्लेषण :-

प्रस्तुत शोध अध्ययन में हम प्राथमिक और द्वितियक तथ्यों से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करेंगे। 25 अक्टूबर 2025 को आई अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष रिपोर्ट में बताया गया है कि घरेलू अर्थव्यवस्था की पहली तिमाही की मजबूत ग्रोथ ने टैरिफ के असर को काफी हद तक संतुलित कर दिया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका के टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर खास असर नहीं दिख रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2025–26 तक दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा। इंडिया की ग्रोथ मौजूदा वित्त वर्ष में चीन से ज्यादा बनी रहेगी। आईएमएफ चीन की विकास दर 2025–26 में 4.8% मान रहा है। आईएमएफ ने भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को भी बढ़ाया है। भारत की जीडीपी चालू वित्त वर्ष में 6.6 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान है। भारत में मज़बूत घरेलू खपत, विनिर्माण गतिविधियां और निजी निवेश में बढ़ोतरी ने इस झटके को काफी हद तक झेल लिया। हालांकि, आईएमएफ ने भारत की 2026-27 की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.2% किया है। भारत की अर्थव्यवस्था वितीय वर्ष 25 में 6.5% की दर से बढ़ी थी और वित्तीय वर्ष 26 के लिए सरकार के 6.3–6.8% के दायरे में बनी हुई है। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स रिपोर्ट के अनुसार 50% टैरिफ का भारतीय कंपनियों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ेगा। हर क्षेत्र पर अमेरिकी कदम के परिणाम एक समान नहीं होंगे। टेक्सटाइल और जेम एवं ज्वेलरी उद्योग पर इसका असर दिख सकता है। वहीं, मजबूत घरेलू मांग और टैरिफ से छूट के कारण फार्मास्यूटिकल्स, स्मार्टफोन और स्टील सेक्टर पर इसका कोई असर नहीं होगा। कैपिटल गुड्स, केमिकल, ऑटोमोबाइल्स, फूड और बेवरेज निर्यात को टैरिफ से कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। टैरिफ में वृद्धि का व्यापक आर्थिक प्रभाव भारत के घरेलू बाजार के बड़े आकार से कम हो सकता है।

एशिया में सबसे बेहतर स्थिति वाला देश :-

राष्ट्र प्रेस में दी गई मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत "एशिया में सबसे बेहतर स्थिति वाला देश"है, क्योंकि देश का वस्तु निर्यात और जीडीपी अनुपात कम है। फिच की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के घरेलू बाजार का बड़ा आकार, जो बाहरी मांग पर निर्भरता को कम करता है, देश को अमेरिकी टैरिफ वृद्धि से बचाए रखेगा, और वित्त वर्ष 26 में अर्थव्यवस्था

Cover Page
INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:12(4), December, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

की वृद्धि दर 6.5% रहने की उम्मीद है। अमेरिकी टैरिफ से निपटने के लिए भारत ने मजबूत तैयारी की है। वाणिज्य मंत्रालय ने टैरिफ से निपटने के लिए'बहु-स्तरीय' रणनीति बना रहा है।

जीएसटी स्लैब में बदलाव का अर्थ :-

भारत सरकार द्वारा एक जुलाई 2017 को 17 प्रकार के टैक्स को खत्म कर एक कर प्रणाली जीएसटी लागू की गई थी। इन सभी टैक्स को जोड़कर लगभग 24% तक टैक्स हो जाता था। सभी को जब खत्म कर जीएसटी लागू किया गया तो सामान्य तौर पर टैक्स 18% हो गया। कुछ दिन पहले हुई जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में मौजूदा चार-स्तरीय ढांचे को दो-स्तरीय ढांचे से बदल दिया गया है। इसमें 18% एवं 5% की मानक दर और कुछ चुनिंदा वस्तुओं तथा सेवाओं पर 40% का सिन टैक्स शामिल है। इससे पहले जीएसटी की 5%, 12%, 18% और 28% की चार दरें थी। जीएसटी दर में बदलाव से आम आदमी की मूलभूत आवश्यकताओं को राहत मिलेगी, इसके चलते रोटी, कपड़ा और मकान से जुड़े उत्पादों पर टैक्स कम होने से खरीदारी बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग और उत्पादन में वृद्धि होगी। ट्रैक्टर के कल-पुर्जों और खाद पर टैक्स घटने से किसानों को भी फायदा होगा। मध्यम वर्ग पर जीएसटी का बोझ कम होने का अनुमान है। इससे घरेलू बाजार में मांग बढ़ सकती है और हम अमेरिका को होने वाले निर्यात का नुकसान इससे पाट सकते हैं। इसमें आम लोगों की जरूरतों रोटी, कपड़ा व मकान का ध्यान रखा गया है। टैक्स कम होने से खरीदारी बढ़ेगी। खरीदारी बढ़ेगी तो बाजार में मांग बढ़ेगी। जीएसटी के मामले में भी भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जीएसटी कलेक्शन के मजबूत आंकड़े घरेलू मोर्चे पर भारतीय अर्थव्यवस्था मज़बूती से आगे बढ़ रही है। मई 2025 में देश का जीएसटी कलेक्शन 16.4% बढ़कर 2,01,050 करोड़ रुपये पहुंच गया। मई 2024 में यह कलेक्शन 1,72,739 करोड़ रुपये था। अप्रैल 2025 में जीएसटी कलेक्शन 2.37 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ। एशियन डेवलपमेंट बैंक की जुलाई 2025 की रिपोर्ट भी कहती है कि घरेलू मांग, अच्छे मानसून और ब्याज दरों में कमी से विकास दर 6.5% तक रहेगी।

स्वदेशी अभियान और टैरिफ :-

भारत सरकार स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण और उसके उपयोग में वृद्धि के नजरिये से देश को आगे बढ़ाने की कार्ययोजना बना रही है। टैरिफ के जवाब में, भारत सरकार ने स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान चलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से 'मेड इन इंडिया' उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की है। स्वदेशी अभियानक के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में दुकानों के मालिकों से अपने प्रतिष्ठानों पर 'स्वदेशी' का बोर्ड लगाने का आग्रह किया है, खासकर त्योहारों के मौसम के लिए सरकार ने विशेष जनजागरूकता उपाय किये। सरकार ने नागरिकों से 'मेड इन इंडिया' उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील भी की है। इसके पीछे सरकार का भरोसा है कि अगर भारतवासी स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी करके स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देते हैं, तो इससे टैरिफ के प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है और राष्ट्र को आर्थिक दबाव से निपटने में सहायता मिलने के आसार हैं। दीपावली और छठ जैसे पर्वों के दौरान यह अभियान काफी तेज रहा, जिसका सकारात्मक प्रभाव भी दिखाई दिया।

मध्यप्रदेश के निर्यात में 6% की बढ़ोतरी :-

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:12(4), December, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

फेडेरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में निर्यात में अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए अब तक का सबसे ज्यादा 66,218 करोड रुपए का निर्यात किया है। निर्यात में 6% की बढ़ोतरी हुई है जो फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग गुड्स और सोया उत्पादों में निर्यात बढ़ने के फलस्वरूप हुई है। मर्केडाइज निर्यात में 66,218 करोड रुपए का योगदान है, स्पेशल इकोनामिक जोन में सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों ने राज्य के निर्यात पोर्टफोलियो में 4038 करोड रुपए का योगदान दिया है। इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास बढ़ने के कारण राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात में मध्यप्रदेश की रैंकिंग 15 से 11 हो गई है। फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग गुड्स और सोया आधारित कृषि उत्पाद मिलाकर मध्यप्रदेश ने विश्व बाजार के प्रतिमानों के अनुसार निर्यात रैंकिंग में बढ़ोतरी की है।

निवेश मित्र औद्योगिक विकास की नीतियां :-

निवेश मित्र औद्योगिक विकास की नीतियां, औदयोगीकरण का बढ़ता आधार मध्यप्रदेश का निर्यात बढ़ने के प्रमुख कारण है। इसके अलावा निर्यात को प्रोत्साहित करने वाली अधोसंरचना में बढ़ोतरी होना और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का मध्यप्रदेश की ओर आकर्षित होने को भी प्रमुख है। आपको बता दें कि पिछले साल तक फार्मास्यूटिकल, एनिमल फीड, मशीनरी, एल्यूमिनियम और टेक्सटाइल पांच ऐसे निर्यात सेक्टर थे जो प्रथम पांच निर्यातकों में शामिल थे। मुख्य रूप से बांग्लादेश, फ्रांस, यूएई और नीदरलैंड में मध्यप्रदेश को निर्यात का बड़ा मार्केट मिला है। फार्मास्यूटिकल और मशीनरी के निर्यात में मध्यप्रदेश के लिए सबसे बड़ा मार्केट यूएस है। मध्यप्रदेश से वर्ष 2024-25 में 11,968 करोड़ रुपए के फार्मास्यूटिकल्स, 6062 रुपए के एनिमल फीड, 4795 करोड़ रुपए के एल्युमिनियम, 4656 रुपए का निर्यात और 5497 रुपए की मशीनरी का निर्यात हुआ। पिछले छह वर्षों से मध्यप्रदेश का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2019-20 में 37,692 करोड़ रुपए, 2020-21 में 47,959 करोड़ रुपए, 2021-22 में 58,407 करोड़ रुपए, 2022-23 में 65,878 करोड़ रुपए, 2023-24 में 65,255 करोड़ रुपए और 2024-25 में 66,218 करोड़ रुपए का निर्यात मध्यप्रदेश से हुआ। इसमें स्पेशल इकोनामिक जोन से हुए निर्यात के आंकड़े भी शामिल है। धार जिला निर्यात में प्रथम है। यहां से 17,830 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ, जबकि इंदौर से 13,500 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ। यहां से फार्मास्यूटिकल, ऑटोमेटिक और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से निर्यात हुआ। उज्जैन ने भी अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2,288 करोड़ रुपए का निर्यात किया है, जिसमें औद्योगिक, एग्रीकल्चर आधारित उत्पाद एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास पर फोकस रखते हुए और व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने से यह सफलता मिली है। इससे न सिर्फ राज्य की आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद मिली है बल्कि देश के कुल निर्यात में भी मध्यप्रदेश का योगदान बढ़ा है। मध्य प्रदेश के प्रमुख निर्यात वाले देशों में अमेरिका, फ्रांस, यूएई, नीदरलैंड,बांग्लादेश शामिल हैं।

मध्यप्रदेश पर टैरिफ प्रभाव का प्रारंभिक अनुमान :-

एक रिपोर्ट के अनुसार टैरिफ लागू होने के तत्काल बाद मध्य प्रदेश की इंडस्ट्री पर भी असर दिखा है। टैरिफ लागू होने के तत्काल बाद से इंदौर से कई देशों का एक्सपोर्ट कम हुआ। शिपिंग कंपनियों ने कम दाम में दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया। फेयर डील इंदौर के मार्केटिंग मैनेजर विनीत कपूर के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका अपने कुल इम्पोर्ट का 70% चीन से, जबकि भारत से मात्र 8% ही इम्पोर्ट करता है। अमेरिका का चीन पर पहले 100 फिर 245% टैरिफ लगाने के

Cover Page
INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:12(4), December, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

चलते अमेरिकी कंपनियों ने चाइना से इम्पोर्ट रोक दिया है। इसके कारण चीन में कंटेनर्स का मूवमेंट रुक गया। चूंकि अमेरिकी कंपनियों ने भारत से इम्पोर्ट भी रोक दिया तो यहां के कंटेनर भी यहीं खड़े रह गए। बढ़े टैरिफ के कारण अमेरिका सप्लाई होने वाले ऑर्डर रुक गए। मध्यप्रदेश एसोसिएशन ऑफ कॉटन प्रोसेसर्स एंड ट्रेडर्स के अध्यक्ष कैलाश अग्रवाल के अनुसार अमेरिकी बाजार में भारतीय टेक्सटाइल्स की पहचान पिछले 5-6 सालों में क्वालिटी और डिजाइन की वजह से बनी है। चीन सहित अन्य देशों की तुलना में भारतीय उत्पादों को ज्यादा पसंद किया जाने लगा है। वर्तमान में प्रदेश से अमेरिका को लगभग 3546 करोड़ डॉलर का टेक्सटाइल और अपैरल निर्यात होता है, जो राज्य के कुल निर्यात का 26% है। लेकिन 50% टैरिफ लगने के बाद यह निर्यात घटकर 1500 करोड़ डॉलर तक सिमटने का अनुमान है। यह प्रदेश के कपास उद्योग और टेक्सटाइल मिलों पर बड़ा संकट की तरह है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। इस साल लगभग 3 करोड़ 15 लाख गांठ कपास उत्पादन का अनुमान है। कपास उत्पादन में मध्यप्रदेश अव्वल राज्य है। यहां से 19 लाख गांठ उत्पादन होने का अनुमान है, जिसमें खरगोन जिला पहले स्थान पर है। खरगोन मंडी से ही करीब 2.8 लाख गांठ आती हैं। टेक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन के प्रदेश सचिव एमसी रावत के मुताबिक, 50% टैरिफ से निर्यात पर बड़ा असर होगा। एक्सपोर्ट को हमें दूसरे देशों की ओर शिफ्ट करना पड़ सकता है। पीथमपुर औद्योगिक संगठन के अध्यक्ष डॉ. गौतम कोठारी के मुताबिक यह नकारात्मक प्रभाव बहुत अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। उद्योगपतियों ने इसके लिए नए रास्ते निकाल लिए हैं। इंदौर और पीथमपुर के उद्योग जगत ने अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, खाड़ी और आसियान जैसे नए बाजारों की तलाश शुरू कर दी है। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष योगेश मेहता के अनुसार कुछ प्रमुख इंजीनियरिंग कंपनियों ने अमेरिका में अपने ब्रांच पहले ही स्थापित कर लिए हैं, जिससे उन्हें तत्काल कोई खास नुकसान नहीं होगा। वे अन्य देशों पर टैरिफ लगने से भारतीय उद्योगों के लिए निर्यात बढ़ाने का यह एक सुनहरा मौका के रूप में देखते हैं।

प्रश्नावली की अंतर्वस्तु विश्लेषण के आधार :-

1. उम्र , 2. जेंडर, 3. शिक्षण स्तर, 4. मूल निवासी, 5. सामाजिक आर्थिक जागरूकता, 6. टैरिफ संबंधी, 7. टैरिफ व्यावसायिक जगत प्रभाव, 8. भारत सरकार का स्वतंत्र निर्णय, 9. टैरिफ का असर और स्वदेशी उत्पाद, 10. स्वदेशी वस्तुओं पर निर्भरता, 11. अमेरिका और स्वदेशी उत्पाद, 12. टैरिफ के प्रभाव से नियंत्रण, 13. जीएसटी स्लैब गति, 14. सरकार की कार्यप्रणाली, 15. मध्यप्रदेश के व्यवसायिक हित

1. उम्र पर अभिमत

इस प्रश्न पर 58 उत्तरदाताओं ने अपना अभिमत दिया। 44.8% उत्तरदाताओं की उम्र 20 से 25 वर्ष थी। 10.3% उत्तरदाताओं की उम्र 26 से 30 वर्ष, 10.3% की उम्र 31 से 35 वर्ष, 6.9% की उम्र 36 से 40, 13.8% की उम्र 41 से 45 वर्ष, 5.2% की उम्र 46 से 50, 5.2% 51 से 55, जबकि 3.2% उत्तरदाताओं की उम्र 55 से 60 वर्ष के बीच थी।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:12(4), December, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

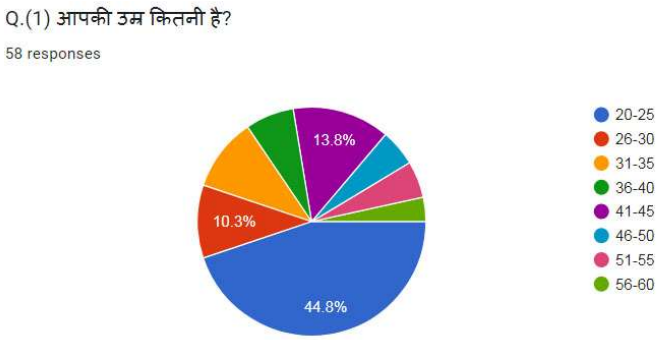

2. जेंडर पर अभिमत

इस प्रश्न पर 58 उत्तरदाताओं ने अपना अभिमत दिया, जिनमें से 69% महिला उत्तरदाता थे, वहीं 31% उत्तरदाता पुरुष थे।

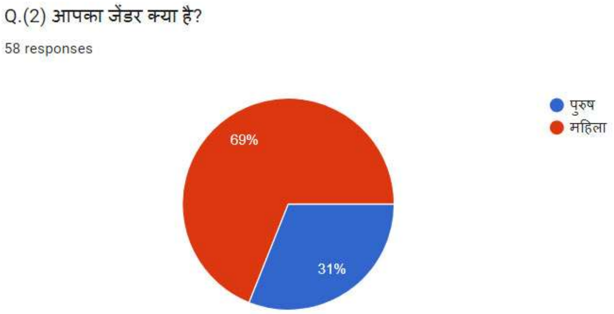

3. शैक्षणिक स्तर पर अभिमत

उत्तरदाताओं के शैक्षणिक अभिमत के बारे में किये गए प्रश्नों के जवाब में पता चला कि 22.4% उत्तरदाता 12वीं पास थे। 19% स्नातक, 34.5 स्नातकोत्तर और 24.1% पी-एच.डी. डिग्रीधारी उत्तरदाता थे।

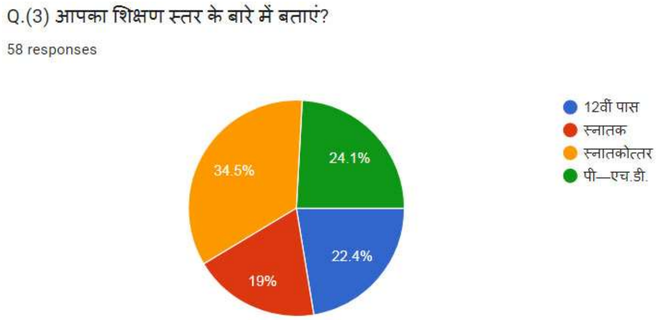

4. मूल निवास संबंधी अभिमत

उत्तरदाताओं के मूल निवास संबंधी प्रश्न पर 58 उत्तरदाताओं ने अपना अभिमत प्रदान किया। 98.3% उत्तरदाताओं ने बताया कि वे मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं, जबकि 1.7 मध्यप्रदेश के बाहरी राज्यों के उत्तरदाता थे।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:12(4), December, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

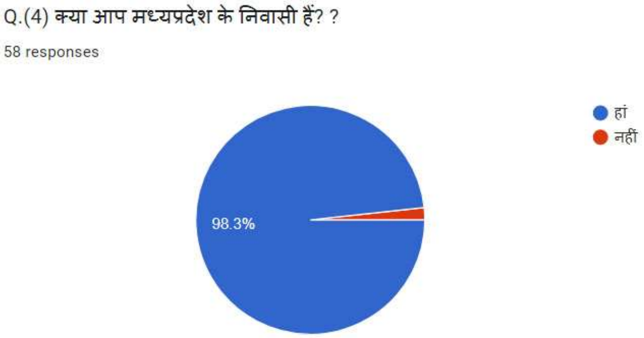

5. सामाजिक आर्थिक जागरूकता पर अभिमत

सामाजिक आर्थिक विषयों के बारे में स्वयं की जागरूकता संबंधी प्रश्न के अभिमत में 58 उत्तर मिले। 74.1% उत्तरदाताओं ने यह माना कि वे 'सामाजिक आर्थिक विषयों के बारे में स्वयं को जागरूक मानते हैं', 1.7% ने खुद को जागरूक नहीं माना और 24.1% उत्तरदाताओं ने खुद को थोड़ा बहुत जागरूक माना।

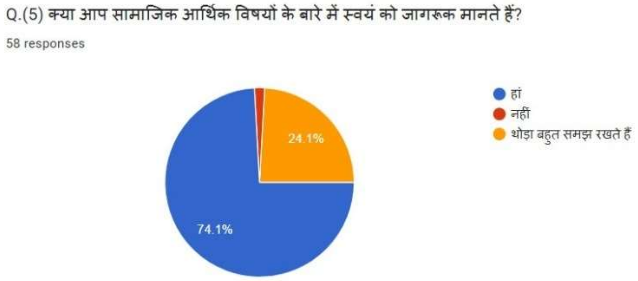

6. अमेरिकी टैरिफ संबंधी अभिमत

'क्या आप जानते हैं कि अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया है? ' इस प्रश्न पर 58 अभिमत प्राप्त हुए। 94.8% उत्तरदाताओं ने जवाब दिया कि वे इस विषय को अच्छे से जानते हैं, वहीं, 5.2% उत्तरदाताओं ने इस विषय पर अनभिज्ञता जताई।

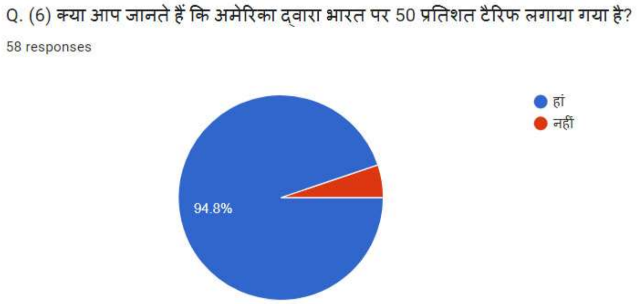

7. टैरिफ का व्यावसायिक जगत प्रभाव अभिमत

'क्या टैरिफ लगाने से भारत के व्यावसायिक जगत में कुछ प्रभाव पड़ने की संभावना है?' संबंधी प्रश्न पर 59 उत्तरदाताओं ने अपना अभिमत प्रदान किया। 57.6% उत्तरदाताओं ने कहा कि इस विषय से प्रभाव पड़ेगा। 5.1% ने कहा कि कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। 16.9% उत्तरदाताओं ने कहा कि थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है। 15.3% ने कहा कि इसका असर बहुत ज्यादा पड़ सकता है। 5.1% ने कहा कि टैरिफ का प्रभाव का सामान्य सा असर पड़ सकता है।

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:12(4), December, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

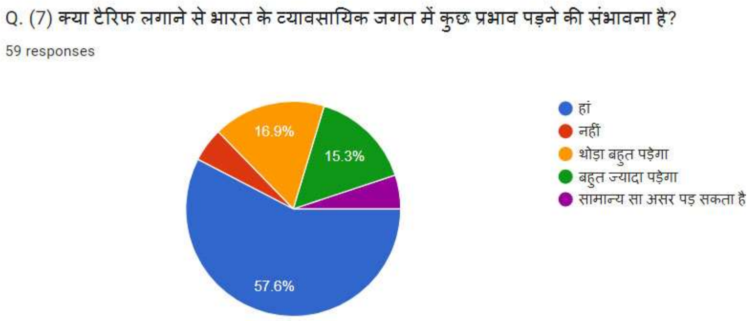

8. भारत सरकार का स्वतंत्र निर्णय

'अमेरिकी दबाव से मुक्त रहकर भारत सरकार द्वारा लिए गए स्वतंत्र निर्णय पर आप क्या सोचते हैं?' संबंधी प्रश्न पर 59 अभिमत प्राप्त हुए। 50.8% उत्तरदाताओं ने कहा कि अमेरिका की मनमानी न मानकर केंद्र सरकार ने मजबूत फैसला लिया है। 30.5% ने इस मुद्दे पर सरकार का साथ देने की बात स्वीकारी। 10.2% उत्तरदाताओं ने कहा कि केंद्र सरकार का कड़ा निर्णय उचित नहीं है। जबकि 8.5% उत्तरदाताओं ने इस विषय पर जानकारी से अनभिज्ञता जताई।

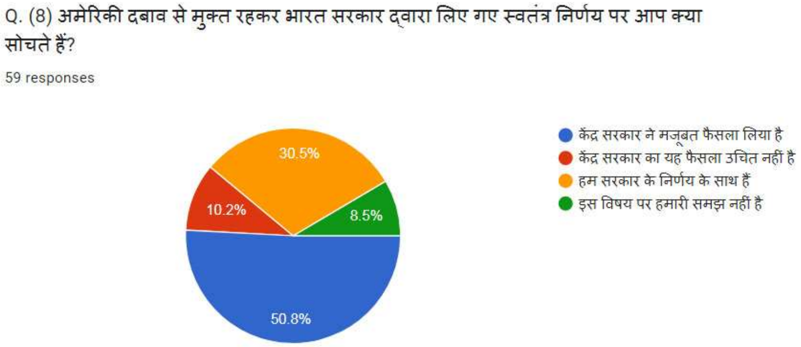

9. टैरिफ का असर और स्वदेशी उत्पाद पर अभिमत

'टैरिफ का असर कम करने के लिए स्वदेशी उत्पादों पर निर्भरता के बारे में क्या सोचते हैं?' इस प्रश्न पर 55 लोगों ने अभिमत दिया। 52.2% उत्तरदाताओं ने कहा- स्वदेशी उत्पादों के जरिये टैरिफ के असर को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। 37.2% ने कहा- स्वदेशी उत्पादों के जरिये टैरिफ के असर को थोड़ा बहुत खत्म किया जा सकता है। जबकि 9.1% उत्तरदाताओं ने माना कि स्वदेशी उत्पादों के जरिए वर्तमान में अमेरिकी टैरिफ से निपटना संभव नहीं है।

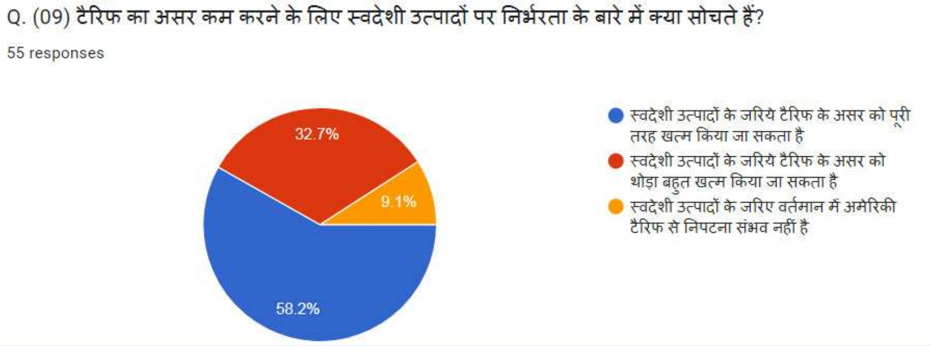

10. स्वदेशी वस्तुओं पर निर्भरता पर अभिमत

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:12(4), December, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

'अगर सरकार स्वदेशी वस्तुओं पर निर्भरता बढ़ाती है तो क्या भविष्य में अमेरिका जैसे देशों से निपटना आसान हो सकता है?' प्रश्न पर 58 लोगों ने अभिमत दिया। 50% उत्तरदाताओं ने जवाब दिया- हां पूरी तरह भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। 27.6% ने जवाब दिया- भारत आत्मनिर्भर बन सकता है, लेकिन अमेरिका पर थोड़ा बहुत आश्रित अवश्य रहना पड़ेगा। 13.8% ने कहा- नहीं पूरी तरह भारत आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है। 8.6% ने जवाब दिया- कुछ स्तर पर अमेरिका पर निर्भरता रखना जरूरी होगा।

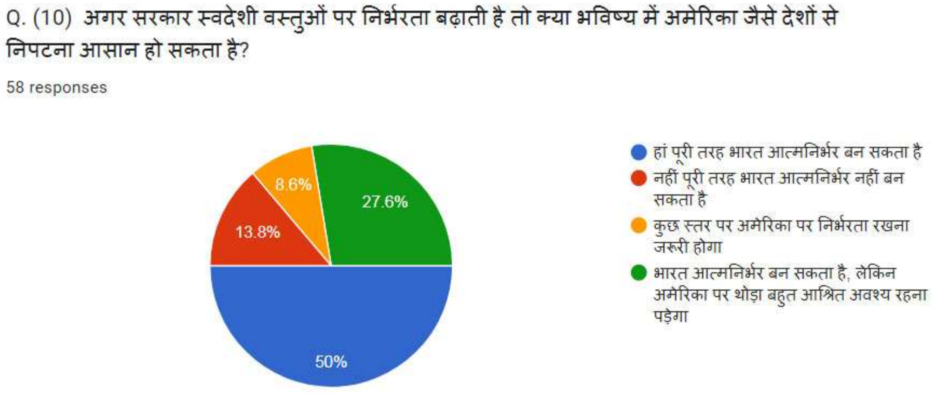

11. अमेरिका और स्वदेशी उत्पाद पर अभिमत

'क्या भारत में पूर्व से ही स्वदेशी उत्पादों के प्रति आत्मनिर्भर होने की पहल प्रारंभ कर देना चाहिए था?' संबंधी प्रश्न पर 58 लोगों ने उत्तर देकर अभिमत प्रदान किया। 79.3% उत्तरदाताओं ने जवाब दिया- हां, यह पहले हो जाना चाहिए था। 10.3% ने कहा- यह उपयुक्त समय है। वहीं, 10.3% उत्तरदाताओं ने जवाब दिया- सरकार ने स्वदेशी अभियान को देर से आगे बढ़ाया।

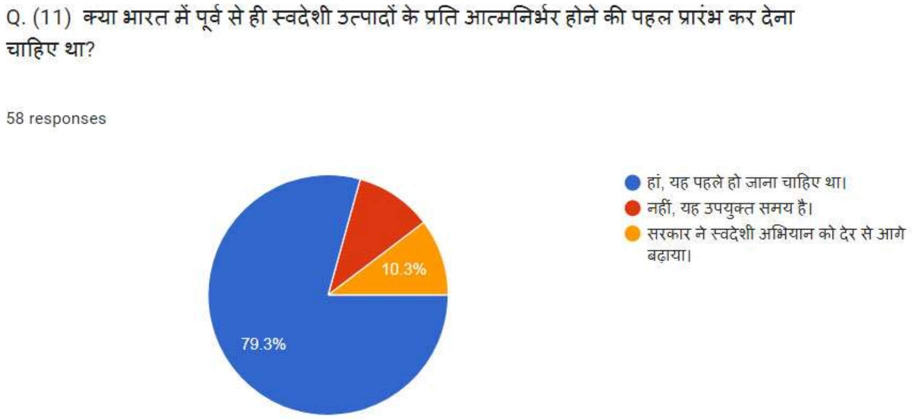

12. टैरिफ के प्रभाव से नियंत्रण पर अभिमत

'क्या आपको लगता है स्वदेशी वस्तुओं के द्वारा भारत भविष्य में अमेरिका के टैरिफ के प्रभाव से पूरी तरह नियंत्रण हासिल कर सकता है?' संबंधी प्रश्न पर 56 लोगों ने उत्तर देकर अपना अभिमत दिया। 42.8% उत्तरदाताओं ने जवाब दिया- हां, स्वदेशी वस्तुओं से भारत अमेरिकी टैरिफ से निपट सकता है। 41.1% ने जवाब दिया- कुछ वर्षों का समय जरूर लग सकता है, लेकिन भारत अमेरिका के टैरिफ से निपट लेगा। 10.7% ने जवाब दिया- नहीं, अमेरिकी टैरिफ से निपटना आसान नहीं है।

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:12(4), December, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

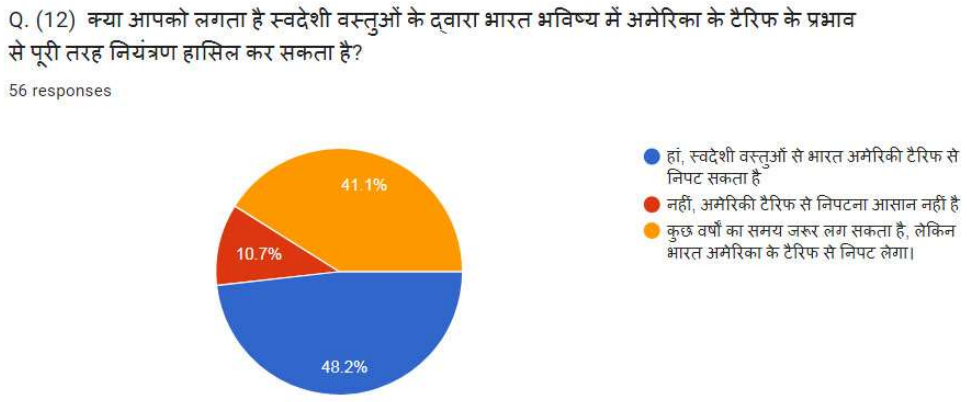

13. जीएसटी स्लैब पर अभिमत

'जीएसटी स्लैब को कम करके कई दरों में कमी करने से क्या स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण में गति आएगी?' संबंधी प्रश्न पर 58 उत्तरदाताओं ने अपना अभिमत प्रदान किया। 62.1% उत्तरदाताओं ने कहा- हां, इससे स्वदेशीकरण बढ़ेगा। 29.3% ने कहा- हां, थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। जबकि 8.6% ने कहा- नहीं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

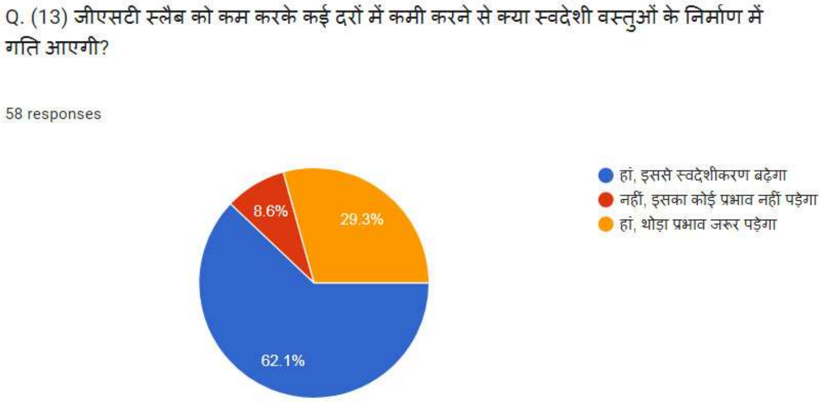

14. सरकार की बेहतर टैक्स कार्यप्रणाली पर अभिमत

'क्या आपको लगता है कि वर्तमान सरकार टैक्स, टैरिफ सहित अन्य मुद्दों पर अच्छा कार्य कर रही है?' प्रश्न के जवाब में 57 लोगों ने अभिमत प्रदान किया। 47.4% उत्तरदाताओं ने कहा- हां अच्छा कार्य हो रहा है। 40.4% लोगों ने इसे सरकार द्वारा संतोषजनक कार्य करना बताया। जबकि 12.3% लोगों ने कहा- नहीं, बिल्कुल अच्छा कार्य नहीं हो रहा।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:12(4), December, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

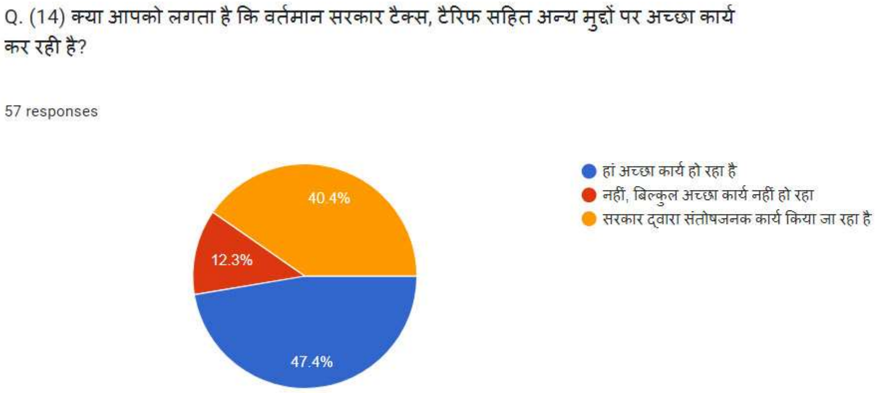

15. टैरिफ और मध्यप्रदेश के व्यवसायिक हित पर अभिमत

'क्या अमेरिकी टैरिफ से वर्तमान में मध्यप्रदेश के व्यवसायिक हितों में कुछ बदलाव दिख रहा है?' संबंधी प्रश्न का 58 उत्तरदाताओं ने अभिमत प्रदान किया। 62.1% उत्तरदाताओं ने अभिमत दिया- भविष्य में कुछ असर देखा जा सकता है। 27.6% उत्तरदाताओं ने कहा- हां अभी से बदलाव दिख रहा है। 5.2% ने कहा- नहीं कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। 5.2% उत्तरदाताओं ने कहा- टैरिफ का मध्यप्रदेश में कोई असर नहीं होगा।

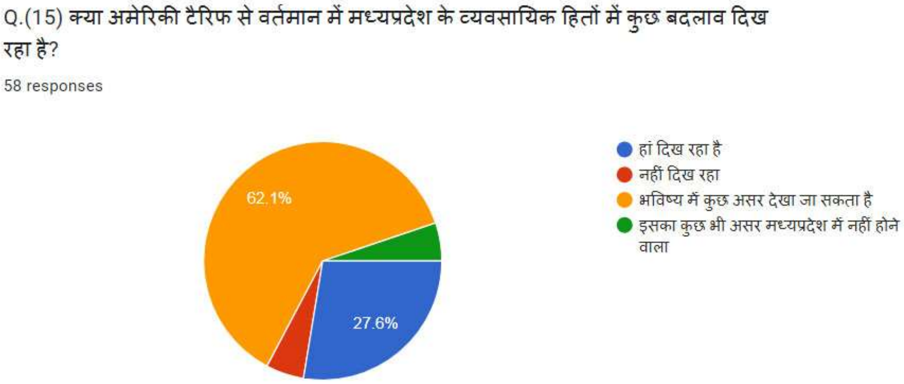

निष्कर्ष :-

'अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के परिप्रेक्ष्य में स्वदेशी वस्तुओं की संभावनाएं, चुनौतियां एवं जनमानस के रुख का अध्ययन (मध्यप्रदेश के संदर्भ में)' विषय पर अध्ययन के लिए प्राथमिक एवं द्वितियक तथ्यों के विश्लेषण में परिणाम सामने आए हैं। प्राथमिक तथ्यों के परिणामों को देखें तो प्रश्नों का जवाब देने वाले नागरिकों का अभिमत देखें तो 57.6% उत्तरदाताओं का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ से भारत के व्यावसायिक जगत में प्रभाव जरूर पड़ेगा। 16.9% उत्तरदाताओं ने कहा कि यह प्रभाव बहुत थोड़ा हो सकता है। 5.1% का जवाब है कि सामान्य प्रभाव देखा जा सकता है, जबकि 5.1% ने कहा कि कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। 50.8% उत्तरदाताओं ने माना है कि भारत अमेरिका के सामने मजबूती से खड़ा रहा, 30.5% लोगों ने कहा कि वे इस मुद्दे पर सरकार का साथ खड़े हैं। परिणाम स्पष्ट हैं कि इस निर्णय से नागरिकों के सामने सरकार की छवि मजबूत हुई है। वहीं, 10.2% लोग मानते हैं कि केंद्र सरकार का कड़ा निर्णय उचित नहीं है। 52.2% लोगों ने स्वदेशी

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:12(4), December, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

उत्पादों को टैरिफ के प्रभाव को पूरी तरह खत्म करने का माध्यम बताया। जबकि 37.2% ने कहा- स्वदेशी उत्पाद इस प्रभाव को मामूली कम कर सकते हैं, 9.1% लोग मानते हैं कि फिलहाल स्वदेशी उत्पादों के जरिए अमेरिकी टैरिफ से निपटना संभव नहीं। वहीं, स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के बाद भविष्य में क्या स्थिति बनेगी, इस पर 50% लोगों का कहना है कि भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सकता है। 27.6% ने जवाब दिया- भारत आत्मनिर्भर तो बन सकता है, लेकिन अमेरिका पर थोड़ा आश्रित रहना पड़ सकता है। 13.8% लोगों की राय है कि स्वदेशी से भारत कभी भी पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। लोगों का मानना है कि सरकार को पूर्व से ही स्वदेशी वस्तुओं पर निर्भरता बढ़ानी चाहिए थी। 79.3% लोगों का कहना है कि यह पहले हो जाना चाहिए था। 10.3% कहते हैं अभी उपयुक्त समय है। 10.3% कहते हैं- स्वदेशी अभियान में देरी हुई। 42.8% उत्तरदाताओं का कहना है कि भविष्य में स्वदेशी वस्तुओं से भारत अमेरिकी टैरिफ से निपट सकता है। जबकि 10.7% लोग अमेरिकी टैरिफ से निपटना आसान नहीं मानते। जीएसटी स्लैब को 18 और 5% के दो स्लैब में करने पर 62.1% नागरिकों का कहना है कि इससे स्वदेशीकरण सुदृढ़ होगा, 29.3% मानते हैं इससे थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। जबकि 8.6% का कहना है कि यह निर्णय प्रभावहीन रह सकता है। भारत की टैक्स प्रणाली पर 47.4% उत्तरदाताओं का मानना है कि सरकार टैक्स, टैरिफ सहित अन्य मुद्दों पर अच्छा कार्य कर रही है। 40.4% लोगों ने इसे संतोषजनक व 12.3% लोगों ने इसे अच्छा नहीं माना। मध्यप्रदेश में टैरिफ का प्रभाव पर लोगों ने अलग-अलग जवाब दिये। 62.1% उत्तरदाताओं ने कहा कि अगर कोई निर्णय नहीं होता है तो भविष्य में कुछ असर देखा जा सकता है, जबकि 27.6% उत्तरदाता मानते हैं कि अभी से बदलाव दिखने लगा है। 5.2% कोई प्रभाव नहीं देखते, जबकि 5.2% का कहना है कि टैरिफ का मध्यप्रदेश में कोई असर नहीं होगा।

द्वितियक तथ्यों के विश्लेषण से पता चलता है कि इसमें स्पष्ट है कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ का तत्काल कुछ प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था में दिख सकता है, लेकिन दीर्घावधि तक इसका प्रभाव नगण्य रह सकता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष रिपोर्ट में घरेलू अर्थव्यवस्था की पहली तिमाही की मजबूत ग्रोथ ने टैरिफ के असर को काफी हद तक संतुलित किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में में भारत को 2025–26 तक दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया गया है। वहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था के 2025-26 में 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है, जो सबसे तेजी से बढ़ते उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में इसकी स्थिति की पुष्टि करता है। हालाँकि, 2026-27 के लिए अपने पूर्वानुमान को मामूली रूप से घटाकर 6.2% कर दिया है, तथा अनुमान लगाया है कि शुरुआती गति के प्रभाव कम होने के कारण विकास में नरमी आएगी। परिणामों से पता चलता है कि वर्तमान में भारत में मज़बूत घरेलू खपत, विनिर्माण गतिविधियां और निजी निवेश में बढ़ोतरी ने टैरिफ के प्रभाव को काफी हद तक नियंत्रित किया है। मॉर्गन स्टेनली की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि भारत "एशिया में सबसे बेहतर स्थिति वाला देश है और वित्त वर्ष 26 में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.5% रहने की उम्मीद जताई है। भारत सरकार द्वारा जीएसटी के मौजूदा चार-स्तरीय ढांचे को दो-स्तरीय 18% एवं 5% की मानक दर में बदला है। इससे नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा और मकान से जुड़े उत्पादों पर टैक्स कम होने से खरीदारी बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग और उत्पादन में वृद्धि होगी। ट्रैक्टर के कल-पुर्जों और खाद पर टैक्स घटने से किसानों को लाभ मिलेगा। भारत सरकार ने स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:12(4), December, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

अभियान चलाया है। 'मेड इन इंडिया' उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी को बढ़ा सकती हैं। इससे टैरिफ के प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है। मध्यप्रदेश के निर्यात में अमेरिकी टैरिफ का कुछ प्रभाव जरूर दिखा है, देश के कपास उत्पादन में अग्रणी मध्यप्रदेश के कपास उद्योग और टेक्सटाइल मिलों पर कुछ संभावित प्रभाव पड़ने की आशंका है। लेकिन फेडेरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट ने राहत भरी खबर दी। मप्र ने वर्ष 2024-25 में निर्यात रैंक में सुधार करते हुए अब तक का सबसे ज्यादा 66,218 करोड रुपए निर्यात किया है,यह निर्यात में 6% की बढ़ोतरी है। इस हिसाब से देखें तो अब राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात में मध्यप्रदेश की रैंकिंग 15 से 11 हो गई है।

संदर्भ :-

1. Kothari, C.R. 2004, Research Methodology Methods and Techniques Second Revised Edition
2. Mishra , Dr. Meenu, Pandey, Dr. Prabhat, 2015, Research Methodology: Tools And Techniques
3. गणेशन, एस. एन., 2009, अनुसंधान प्रविधि सिद्धांत और प्रक्रिया
4. शोध विधियां तथा सांख्यिकी, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद’’
5. गुप्ता, उमाकांता, जोशी, वृजरतना, अनुसंधान, स्वरूप और आयाम
6. https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/donald-trump-pm-modi-trade-deal-nicest-looking-guy-us-india-relations/articleshow/124889440.cms?from=mdr
7. https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1579173
8. https://www.zeebiz.com/hindi/economy/india-fy26-gdp-growth-to-stay-strong-despite-us-tariff-gst-reforms-inflation-rbi-rate-cut-237324
9. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2118182
10. https://www.bbc.com/news/articles/cn93e12rypgo
11. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2178929
12. https://www.aajtak.in/business/news/story/india-us-trade-deal-trump-tariff-reduce-russia-oil-agriculture-tutd-dskc-2363568-2025-10-22
13. https://www.aajtak.in/business/news/story/india-exports-to-china-surged-22-percent-first-half-amid-us-tariff-tension-tutc-dskc-2368340-2025-10-27
14. https://hindi.news18.com/news/business/economy-imf-report-exposes-impact-of-us-tariff-on-india-gdp-growth-forecast-raised-ws-kl-9775863.html
15. https://www.amarujala.com/business/business-diary/how-will-india-deal-with-the-loss-of-50-us-tariff-know-the-five-fronts-from-where-the-country-will-get-help-2025-08-27?pageId=1
16. https://ndtv.in/business-news/india-solidly-prepared-to-deal-with-us-tariffs-know-what-is-the-plan-of-the-commerce-ministry-9197056
17. https://ddnews.gov.in/report-claims-us-tariff-hike-will-not-have-major-impact-on-indian-economy/
18. https://mp.punjabkesari.in/national/news/mp-will-suffer-the-most-from-trump-tariff--cotton-industry-will-suffer-huge-los-2204649#google_vignette
19. https://www.bhaskar.com/local/mp/indore/news/the-impact-of-trumps-tariff-war-is-also-in-madhya-pradesh-134860278.html
20. https://www.mpinfo.org/Home/TodaysNews?newsid=%C2%B2%C2%B0%C2%B2%C2%B5%C2%B0%C2%B8%C2%B1%C2%B0%C3%8E%C2%B4%C2%B1&fontname=%C3%8D%C3%A1%C3%AE%C3%A7%C3%A1%C3%AC&LocID=32&pubdate=08/10/2025